उच्चशिक्षा में दाखिले के लिये कहीं पर भीड़भाड़, और कहीं पर सन्नाटा क्यों?

डा. हरिवंश चतुर्वेदी,
निदेशक, बिमटेक

देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश–प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 1922 में स्थापित इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 16 संकाय, 86 विभाग और 77 संबद्ध कालेज हैं जिनके विभिन्न कोर्सों में उपलब्ध 70 हजार सीटों के लिये लगभग 2.5 लाख प्रवेशार्थी हर साल आवेदन करते हैं। देश के हर कोने से प्रतिभाशाली विद्यार्थी यह सपना लेकर इन दिनों दिल्ली पहुंचते हैं कि किसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी नामी गिरामी कालेज में दाखिला मिल सके।

दिल्ली की तरह चेन्नई, बंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चण्डीगढ़ जैसे महानगरो के विश्वविद्यालयों और कालेजों में भी इसी तरह की भीड़ भाड़ दिखाई देती है। इन दिनों देश के लाखों सुशिक्षित और प्रबुद्ध अभिभावकों की चिंता का प्रमुख विषय उनके बच्चों का बड़े शहर के किसी अच्छे कालेज में मनचाहे कोर्स में दाखिला ना मिल पाना है। प्रवेश सूची के जारी होने तक उनकी सांस में सांस अटकी रहती है कि आखिर मनचाहे कालेज में उनके बच्चे का दाखिला हो पायेगा या नहीं?

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का सीजन तो अभी शुरू हुआ है और अगले माह के अंत तक खत्म हो पायेगा, किन्तु पूरे देश में यह प्रक्रिया सितंबर अंत तक चलेगी। क्या पूरे देश में सभी जगह और सभी कोर्सों में ऐसी ही भीड़–भाड़ देखी जा रही हैं? क्या सभी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा और छवि वैसी है जैसी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की है? देश में ऐसे विश्वविद्यालय, कालेज और कोर्स भी है जहाँ पर पिछले एक दशक से प्रवेशार्थियों की कमी चली आ रही है। विज्ञान, लिबरल आर्टस और समाज विज्ञान की तुलना में सामान्यताः इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सो को बहुत पॉपूलर माना जाता रहा है क्योंकि लाखों युवाजन हर वर्ष इन कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठतें हैं। किन्तु पिछले एक दशक से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एम.सी.ए. के अनेकों कॉलेज प्रवेशार्थी न मिलने के कारण बन्द होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं।

हमारा देश विविधताओं का संगम माना जाता है। सामाजिक–आर्थिक विविधताओं ओर असमान विकास के कारण यहां हर क्षेत्र में गहरे विरोधाभास दिखाई देते है। उच्चशिक्षा भी इसमें एक बड़ा उदाहरण है। हमारे शिक्षाविदों, नीति निर्धारकों और औद्योगिक जगत के नियोक्ताओं को यह देखना चाहिये कि देश के कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रवेशार्थियों की भीड़ कभी कम क्यों नहीं होती और दूसरी तरफ सैंकड़ों कालेजो में सन्नाटा क्यों है? क्या इस के लिये मुख्य रूप से हमारी दोहरी शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार नहीं जिसमें संपन्न वर्ग और आम आदमी के बच्चों के लिये अगल अलग क्वालिटी के कालेज और विश्वविद्यालय चलाये जाते हैं? क्या केन्द्र व राज्य सरकारें सरकारी विश्वविद्यालयों व कालेजों को समुचित वित्तीय सहायता दे पा रही हैं?

1947 में आजादी पाने के समय भारत में 25 विश्वविद्यालयों और 700 कॉलेजों मे सिर्फ एक लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। आजादी के बाद के 70 वर्षो में उच्चशिक्षा के अवसरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज देश के 858 विश्वविद्यालयों में और 45000 कॉलेजों में 3.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी उच्चशिक्षा पा रहे हैं। अगर उच्चशिक्षा में क्वालिटी के पैमाने पर चुनाव किया जाये तो बमुश्किल 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय और कॉलेज ही उस पर खरे उतरेंगे। ये वही कॉलेज हैं जो ऐतिहासिक विरासत, कुशल प्रबंध, ब्रांडिग, अलुमनाई या स्वायत्तता के कारण अपनी धाक जमाये हुए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी लाखों प्रवेशार्थियों को प्रतिवर्ष आकर्षित करते हैं। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के डिग्रीधारियों को समाज, सरकार और उद्योगजगत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जे.एन.यू., बी.एच.यू., ए.एम.यू, जामिया मिलिया, कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विश्वविद्यालयों की आकर्षण शक्ति के कई कारण है। इनमें से हरेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पास अमूल्य ऐतिहासिक विरासत है। कई विश्वविद्यालय 100 वर्षो से ज्यादा पुराने हैं जिनके लाखों अलुमनाई देश और दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में यश प्राप्त कर चुके हैं। इन विश्वविद्यालयों की कामयाबी के अन्य कारण केन्द्रीय सरकार से प्रचुर फण्ड प्राप्त होना, विशाल कैम्पस, शिक्षक व छात्र वर्ग में विविधता, एडमिशन में पारदर्शिता और राजनैतिक दखलंदाजी से मुक्ति आदि हैं। ऐसा नहीं है कि इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोई कमी न हो। परन्तु ज्यादातर स्थानों पर जागरूक

शिक्षक समुदाय के स्वायत्तता को लेकर बहुत मुखर रवैय्ये से राजनैतिक दखलंदाजी पर नियंत्रण बना रहता है।

भारत की उच्चशिक्षा में श्रेष्ठता के शिखरों पर कोई भी चर्चा, आईआईटी और आईआईएम संस्थानों की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कारणों का विश्लेषण किये बिना अधूरी होगी। आईआईटी मुंबई, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर और मद्रास की इंजीनियरिंग शिक्षा की उत्कृष्टता का लोहा सारी दुनिया में माना जाता है। इन संस्थानों से निकले बी टेक, एम टेक एंव पीएचडी उपाधिधारियों को दुनिया के हर देश में औद्योगिक व शैक्षणिक जगत में सम्मान मिला है। आईआईटी अब एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्ड़ है, जिसने भारतीय सूचना उद्योग को भी एक ब्राण्ड बना दिया है। आईआईटी की ऐतिहासिक सफलता के कारणों में मुख्य रूप से इनकी स्वायत्तता, शोध वे अनुसंधान पर जोर देना और उद्योगों की जरूरतों पर ध्यान देना शामिल है।

जहाँ तक आईआईएम संस्थानों का सवाल है, अहमदाबाद, कोलकाता और बंगलौर में स्थापित प्रथम तीन संस्थान विश्वव्यापी प्रसिद्धि पा चुके हैं। इनके अलावा डेड़ दर्जन अन्य आईआईएम संस्थान अभी ख्याति अर्जित करने के लिये प्रयासरत हैं। आईआईएम अहमदाबाद और कोलकाता अपनी स्थापना के 56 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 1961 में जब आई.आई.एम., अहमदाबाद की स्थापना हो रही थी तो उसके संस्थापक विक्रम साराभाई और प्रथम निदेशक रवि मथाई ने एक ऐसे संस्थान की कल्पना की जो भारतीय विश्वविद्यालयों की जड़ता, परिवर्तनविहीनता और लकीर के फकीर रवैय्ये से मुक्त होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 नेहरू भी इन दोनों की राय से सहमत थे। नजीतन आईआईएम एक स्वायत्तशासी संस्थानों के रूप में स्थापित हुए जिन पर किसी यूनिवर्सिटी का नियंत्रण नहीं था। इन का प्रबंध अधिकांशतया निदेशक व फैकल्टी को सोंपा गया जो प्रबन्ध मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। वर्ष 2017 में आईआईएम बिल को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इन संस्थानों को पूर्णतया स्वायत्तशासी बना दिया गया है।

1991 के बाद, आर्थिक उदारीकरण के दौर में तकनीकी व पेशेवर शिक्षा का तेजी से विकास हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था को इंजीनियरों, प्रबंधकों और डाक्टरों की ज्यादा जरूरत थी। इस दौर में तकनीकी व पेशेवर शिक्षा में ज्यादातर संस्थान निजी क्षेत्र में स्थापित हुए। आज इंजीनियरिंग, प्रबंध, मेडीकल, फार्मेसी आदि क्षेत्रों में

प्रतिशत से ज्यादा संस्थान निजी क्षेत्र में हैं। देश के किसी भी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आप को ऐसे होर्डिंग्स मिल जायेंगे जो कि बीटेक, एमबीए जैसे कोर्सो के लुभावने विज्ञापन दिखाते हैं और 100% प्लेसमेंट के दावे करते है। इनमें से ज्यादातर संस्थान व्यावसायिक उद्देश्यों पर चलाये जाते हैं और उच्चशिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इन निजी संस्थानों के संचालन का एक विशिष्ट मॉडल है जिसमें संस्थान की आकर्षक बिल्डिंग बनाने, टीवी चैनलों व प्रिंट मीडिया में मंहगे विज्ञापन करने और एडमिशन मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैरिट पर आधारित प्रवेश, अच्छी फैकल्टी, गवर्नेंस, वित्तीय पारदर्शिता, शोध व अनुसंधान आदि महत्वपूर्ण तत्व आमतौर पर उपेक्षित रहते हैं। नितांत व्यावसायिक ढंग से चलाये जाने वाले कालेजों और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों से अब मध्यवर्गीय परिवारों का मोहभंग शुरू हो चुका है और एक हजार से अधिक इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कालेजों को एआईसीटीई द्वारा बन्द किया जा चुका है।

निजी क्षेत्र के सभी संस्थान व्यावसायिक मॉडल पर नहीं चलाये जाते। इनमें से अनेक संस्थान देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, व्यवसायीयों, पेशेवरों तथा चैरिटेबिल ट्रस्टों व सोसायटियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। चूंकि इनके संस्थापकों ने दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखा, ऐसी संस्थाएं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति स्थापित करने में कामयाब रहीं हैं। बिट्स–पिलानी, बीआईटी मेसरा, थापर, पटियाला, मनीपाल यूनिवर्सिटी, मनीपाल, वीआईटी, वेल्लौर, पी एस जी, कोयम्बटूर, निरमा व धीरूभाई संस्थान, अहमदाबाद, निट्टे, मंगलौर, जेएसएस, मैसूर आदि ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां विश्वस्तरीय क्वालिटी की तकनीकी व पेशेवर शिक्षा प्रदान की जा रही है। चूंकि सरकार के पास सभी वर्गों को उच्चशिक्षा प्रदान करने के संसाधन नहीं हैं, ऐसी निजी संस्थानों को प्रोत्साहना देना आवश्यक होगा।

आजादी के 70 वर्षों बाद, हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारे कुछ विश्वविद्यालय, तकनीकी और पेशेवर संस्थान विश्वस्तरीय क्वालिटी की उच्चशिक्षा प्रदान कर रहें हैं। कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम एवं बिट्स पिलानी जैसे निजी संस्थान इसके उदाहरण हैं। हमारी ज्वलंत समस्या राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में दी जा रही स्तरहीन शिक्षा की है। हमारे 90 प्रतिशत युवाओं को जिस तरह डिग्रीयां बांटी जा रही हैं, उससे उनके जीवन को कोई दिशा नहीं मिल सकेगी। भारत में उच्चशिक्षा का प्रमुख मुद्दा बमुश्किल 20 प्रतिशत प्रवेशार्थियों को

क्वालिटी शिक्षा मिलपाना है। जब तक उच्चस्तरीय क्वालिटी संस्थानों का विस्तार नहीं होगा, कुछ खास विश्वविद्यालयों और कालेजों में भीड़भाड़ की समस्या बनी रहेगी।